

## II. समग्र मांग

देशी मांग\* से प्रेरित वृद्धि की प्रक्रिया जारी रही और निजी उपभोग व्यय में मजबूत वृद्धि और वृद्धि में स्थिर पूंजी निर्माण का उच्च योगदान इसकी विशेषता थी। हाल के कुछ महीनों में राजकोषीय मजबूती और सरकारी व्यय में गिरावट दर्शाते हुए वृद्धि में सरकारी उपभोग व्यय में कमी आई। कंपनियों की बिक्री में वृद्धि उच्च बनी रही जबकि आय में सुधार हुआ जो मांग में उछाल दर्शाता है। चूंकि बाह्य क्षेत्र की संभावना सामान्यतः चालू खाते के घाटे में वृद्धि दर्शाती है, अतः वृद्धि में निवल निर्यात का योगदान नगण्य रह सकता है।

### निजी उपभोग व्यय और सरकारी पूंजीगत व्यय वर्ष की पहली छमाही में वृद्धि के प्रमुख प्रेरक रहे हैं

II.1 2010-11 की पहली छमाही के दौरान, वृद्धि का बल जीडीपी के व्यय पक्ष से आया था जो कि निजी उपभोग व्यय और सकल

स्थिर पूंजी निर्माण में वृद्धि से उपजा था (सारणी II.1 और चार्ट II.1)। निजी अंतिम उपभोग व्यय तेजी से बढ़ा जो आंशिक रूप से कृषि-वृद्धि में तेजी दर्शाता है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण ने भी उच्च वृद्धि दर्शाई जिसे कंपनी क्षेत्र के मजबूत निष्पादन और सरकारी पूंजीगत व्यय में तेज वृद्धि से सहायता मिली थी। समग्र रूप से, बाजार मूल्य पर वास्तविक जीडीपी 2010-11 की पहली छमाही के दौरान 10.4 प्रतिशत बढ़ी जो कि कारक लागत वास्तविक जीडीपी में 8.9 प्रतिशत वृद्धि से अधिक थी। वृद्धि दर में अंतर ने वर्ष में मजबूत समग्र और औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि से सरकार को प्राप्त उच्च निवल परोक्ष कर दर्शाया। इसके अलावा, 2010-11 की पहली तिमाही के व्यय पक्षीय आंकड़ों में काफी सुधार से, सकल स्थिर पूंजी निर्माण की प्रवृत्ति और आइआइपी में पूंजीगत माल घटक अब चालू राजकोषीय वर्ष की पहली छमाही के लिए बेहतर रूप से दिशाबद्ध है।

सारणी II.1: जीडीपी का व्यय पक्ष (2004-05 मूल्य)

	(प्रतिशत)									
	2008-09@	2009-10#	2009-10				2010-11		2009-10	2010-11
			ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>वृद्धि दर</b>										
बाजार मूल्यों पर वास्तविक जीडीपी	5.1	7.7	5.6	6.6	7.3	11.2	10.3	10.6	6.1	10.4
कुल अंतिम खपत व्यय	8.3	5.3	5.9	9.8	4.8	2.6	8.0	9.3	7.8	8.7
(i) निजी	6.8	4.3	4.3	6.7	5.3	2.6	7.8	9.3	5.5	8.6
(ii) सरकारी	16.7	10.5	15.4	30.2	2.5	2.1	9.0	9.2	22.4	9.1
सकल अचल पूंजी निर्माण	4.0	7.2	3.1	4.0	8.8	17.7	19.0	11.1	3.6	14.9
स्टॉक में परिवर्तन	-61.2	5.9	-0.8	3.5	8.7	11.1	15.3	12.4	1.4	13.8
निवल निर्यात	40.2	-9.7	13.2	-7.6	-0.3	-113.4	12.2	-2.9	0.1	3.4
<b>सापेक्षिक हिस्सा</b>										
कुल अंतिम खपत व्यय	70.9	69.4	73.1	72.6	73.4	62.3	71.6	71.7	72.8	71.6
(i) निजी	59.5	57.6	61.6	61.3	60.4	51.1	60.3	60.6	61.4	60.4
(ii) सरकारी	11.5	11.8	11.4	11.3	13.1	11.2	11.3	11.2	11.4	11.2
सकल अचल पूंजी निर्माण	32.9	32.8	32.4	34.3	31.9	34.6	35.0	34.4	33.4	34.7
स्टॉक में परिवर्तन	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3
निवल-निर्यात	-6.1	-5.1	-5.7	-7.8	-6.7	0.4	-5.8	-6.8	-6.7	-6.3
ज्ञापन:									करोड़ ₹	
बाजार मूल्य पर वास्तविक जीडीपी	44,65,360	48,07,222	10,85,993	11,08,537	12,42,858	13,39,454	11,97,587	12,25,554	21,94,530	24,23,141

@ : त्वरित अनुमान # : संशोधित अनुमान।

नोट : चूंकि प्रमुख मद्दे ही सारणी में शामिल की गई है, इसलिए आंकड़ों का जोड़ 100 नहीं होगा।

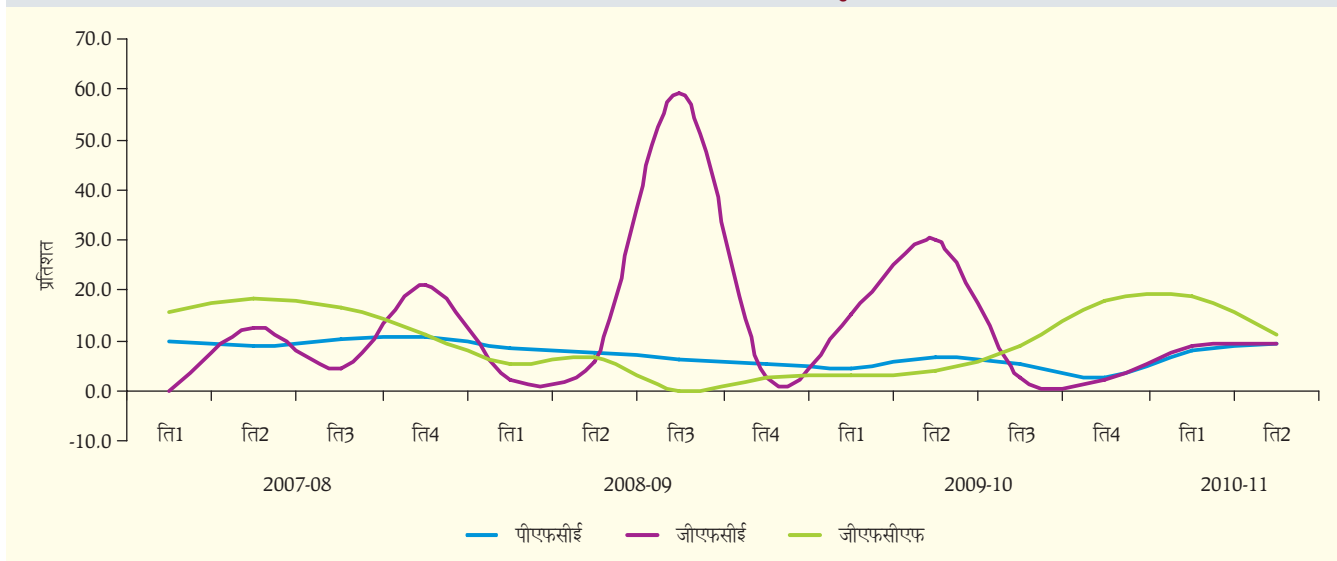
स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन।

\* जीडीपी के व्यय पक्ष के आंकड़ों द्वारा आंकी गई मांग।

## मौद्रिक नीति वक्तव्य 2010-11

समष्टिआर्थिक और मौद्रिक गतिविधियां  
तीसरी तिमाही की समीक्षा 2010-11

चार्ट II.1: तिमाही वार वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि



**समग्र वृद्धि में सरकारी अंतिम उपभोग व्यय और निवल निर्यात का योगदान दर्शाता है कि राजकोषीय स्थिति में सुधार हुआ है और चालू खाते का घाटा बढ़ा है**

II.2 सरकारी अंतिम उपभोग व्यय लगातार तेजी से बढ़ता रहा किंतु पिछले वर्ष की उच्च वृद्धि की तुलना में यह काफी कम था जो राजकोषीय समेकन प्रक्रिया वापस आना दर्शाता है (सारणी II.1)।

II.3 निवल निर्यात का योगदान लगातार दूसरी तिमाही में भी कम हुआ, हालांकि यह फिर भी सकारात्मक बना रहा यहां तक कि माल और सेवा खाते का घाटा बना हुआ था (चार्ट II.2)।

**सरकारी व्यय संयोजन पूंजीगत व्यय की ओर अंतरित हुआ**

II.4 केंद्र ने संकट से प्रेरित विस्तारी राजकोषीय नीति रुझान से क्रमिक रूप से बाहर निकलने के एक भाग के रूप में 2010-11 की व्यय वृद्धि में तेज कमी लोन का वचिार किया था। किंतु, 2010-11 के दौरान (अप्रैल-नवंबर) की प्रगति व्यय में अनुमानित से अधिक वृद्धि दर्शाती है। व्यय के पूंजीगत घटक ने मजबूत वृद्धि दर्शाई और बुनियादी सुविधा के बढ़ते अंतर को मिटाने के लिए इसके जारी रहने की आवश्यकता है। किंतु, कुल व्यय वृद्धि 2009-10 की इसी अवधि के दौरान दर्ज वृद्धि से काफी कम थी क्योंकि सरकार ने अगस्त 2010 से अपना व्यय कम किया था। अनुमान से अधिक राजस्व प्राप्ति के आधार पर उपलब्ध राजकोषीय अवसर के आधार पर सरकार प्राथमिकताप्राप्त

क्षेत्र में अपना व्यय बढ़ाना चाहती है जिससे मांग पर दबाव बढ़ सकता है।

II.5 2010-11 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान अनुमान से अधिक राजस्व प्राप्ति का कारण अपेक्षा से अधिक कर और करेतर वसूली थी। 3जी और ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस (बीडब्ल्यूए) स्पेक्ट्रम नीलामी के माध्यम से हुई प्राप्तियों के रूप में व्यापक करेतर राजस्व के अलावा सकल कर राजस्व भी काफी (26.8 प्रतिशत) बढ़ा जबकि 2009-10 (अप्रैल-नवंबर) में गिरावट (7.8 प्रतिशत) हुई थी। सीमा शुल्क (64.2 प्रतिशत) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (37.3

चार्ट II.2: वास्तविक जीडीपी वृद्धि में योगदान



प्रतिशत) से प्राप्त राजस्व में काफी वृद्धि हुई और साथ ही निजी आय कर वसूली (11.8 प्रतिशत) और कंपनी कर वसूली (19.9 प्रतिशत) में भी भारी वृद्धि हुई है जो मुख्यतः देशी आर्थिक कार्यकलापों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में तेजी के साथ ही राजकोषीय बहिर्गमन के एक भाग के रूप में परोक्ष कर कटौती आंशिक रूप से वापस लेना दर्शाती है।

II.6 सरकार अपना राजकोषीय घाटा 2010-11 में जीडीपी के 5.5 प्रतिशत तक लाने के प्रयास कर रही है। इसके प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के मध्य-वर्षीय लक्ष्य राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंध (एफआरबीएम) नियमावली, 2004 लागू होने के बाद से पहली बार पूरे हुए थे जिसमें राजस्व प्राप्तियों में तेज उछाल से सहायता मिली थी। 2010-11(अप्रैल-नवंबर) के दौरान केंद्र सरकार के वित्त में वृद्धि 2009-10 की तुलना में व्यय में कम वृद्धि और कर तथा करेतर राजस्व में देखी गई तेज वृद्धि दर्शाती है। परिणामतः, 2010-11(अप्रैल-नवंबर) के दौरान राजस्व घाटा (आरडी) और सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में समग्र संदर्भ में और बजट अनुमान के अनुपात के रूप में काफी कम थे।

### समावेशक वृद्धि के लिए उच्च विकास व्यय आवश्यक है

II.7 सरकारी व्यय की क्षेत्र-वार रूपरेखा 2010-11(अप्रैल-नवंबर) के दौरान कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य में व्यय में अनुमानित से अधिक वृद्धि दर्शाती है जो समावेशक और टिकाऊ

वृद्धि के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है। अधिक राजस्व से बनी उच्च संसाधन उपलब्धता ने इन प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों के लिए अधिक परिव्यय आबंटित करने के लिए राजकोषीय स्थिति उत्पन्न की है जो कि अनुदान के लिए सरकार की अतिरिक्त अनुपूरक मांग में दिखता है। समावेशक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कम मुद्रास्फीति मुख्य कारक होने से सामाजिक व्यय से उपजी उच्च मांग आपूर्ति पक्ष की आवश्यक मदों की वृद्धि दर बढ़ाने की आवश्यकता दर्शाती है।

### मध्यावधि में राजकोषीय मजबूती के प्रति जोखिम और राजकोषीय मजबूती की गुणवत्ता महत्वपूर्ण चिंताएं हैं

II.8 केंद्र सरकारी वित्त मध्यावधि राजकोषीय नीति वक्तव्य (एमटीएफपीएस) के अनुरूप होने के बावजूद, आरडी और जीएफडी के तरहवें वित्त आयोग के लक्ष्य (जीडीपी के क्रमशः शून्य प्रतिशत और 3.0 प्रतिशत) पूरे करने के लिए 2013-14 तक तेज सुधार आवश्यक होगा। सरकार जानती है कि 2013-14 तक आरडी की परिकल्पित समाप्ति कठिन है। इसके अलावा, सरकार के मध्यावधि विश्लेषण, 2010-11 में दिए संकेतानुसार, पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण के मध्यावधि लक्ष्य पूरे करने के लिए उधार राशि को उपयोग में लाना होगा। आर्थिक और प्रयोजनमूलक वर्गीकरण के अनुसार, 2010-11 के दौरान केंद्र सरकार का प्रशासनिक व्यय और सकल पूंजी निर्माण में किया जाने वाला विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का व्यय कम रहने (जीडीपी का 1.0 प्रतिशत) का अनुमान है। इसके अलावा, बढ़ते

सारणी II.2: अप्रैल-नवंबर के दौरान केंद्र सरकार के वित्त

मद	राशि (₹ करोड़)		बजट अनुमान का प्रतिशत		वृद्धि दर (प्रतिशत)	
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7
1. राजस्व प्राप्ति	3,07,125	4,76,716	50.0	69.9	-2.5	55.2
i) कर राजस्व (निवल)	2,32,873	2,96,634	49.1	55.5	-8.2	27.4
ii) करेतर राजस्व	74,252	1,80,082	52.9	121.6	20.9	142.5
2. ऋणेतर पूंजी प्राप्ति	8,326	27,449	155.8	60.8	215.4	229.7
3. योजनेतर व्यय	4,47,995	4,79,771	64.4	65.2	25.1	7.1
जिसमें से:						
i) ब्याज भुगतान	1,19,504	1,34,544	53.0	54.1	7.0	12.6
ii) रक्षा	78,955	86,404	55.7	58.6	50.2	9.4
iii) प्रमुख सव्बिडियां	90,766	90,137	85.6	82.6	-8.1	-0.7
4. योजना व्यय	1,73,677	2,10,916	53.4	56.5	27.6	21.4
5. राजस्व व्यय	5,65,027	6,16,874	63.0	64.3	23.8	9.2
6. पूंजी व्यय	56,645	73,813	45.8	49.2	49.9	30.3
7. कुल व्यय	6,21,672	6,90,687	60.9	62.3	25.8	11.1
8. राजस्व घाटा	2,57,902	1,40,158	91.2	50.7	82.4	-45.7
9. सकल राजकोषीय घाटा	3,06,221	1,86,522	76.4	48.9	73.5	-39.1
10. सकल प्राथमिक घाटा	1,86,717	51,978	106.4	39.2	188.0	-72.2

स्रोत : महा लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय।

## मौद्रिक नीति वक्तव्य 2010-11

समष्टिआर्थिक और मौद्रिक गतिविधियां  
तीसरी तिमाही की समीक्षा 2010-11

अंतरराष्ट्रीय तेल और उर्वरक के मूल्यों के कारण सब्सिडी में और वृद्धि की संभावना है। अंत में, वैश्विक अनिश्चितता, विशेष रूप से यूरोप में, राजकोषीय मजबूती के प्रति मुख्य अधोमुखी जोखिम बनी हुई है।

II.9 सुदृढ़ीकरण के वर्तमान चरण में समायोजन की गुणवत्ता और साथ ही पर्याप्त राजकोषीय व्यवस्था बनाने पर होना चाहिए ताकि वृद्धि और मुद्रास्फीति के प्रति भावी प्रतिकूल आघातों से निपटा जा सके। 2010-11 के लिए सोचा गया राजकोषीय सुधार काफी हद तक किसी विशेष मदों (जैसे कि टेलीकॉम स्पेक्ट्रम नीलामी और विनिवेश प्राप्तियां) पर निर्भर है। इसके अलावा, 2010-11 में अनुमानित राजकोषीय सुधार का काफी भाग भुगतान और पेंशन की बकाया राशि संबंधी व्यय अनुमान से कम होने और ऋण माफी योजनाओं के कारण बचत से ही होगा। किंतु, टिकाऊ राजकोषीय मजबूती के लिए उपाय करने होंगे ताकि राजस्व वसूली टिकाऊ आधार पर बढ़े और योजनेतर राजस्व व्यय कम करने पर फोकस रखते हुए आवर्तित व्यय को उचित सीमा में रखना होगा।

### राज्य सरकारों के वित्त में सुधार होने से संयुक्त राजकोषीय अंतर कम होने की संभावना है

II.10 पिछले दो वर्षों की गिरावट के बाद, राज्य सरकारों का समेकित राजस्व घाटा और सकल राजकोषीय घाटा 2010-11 (बीई) में कम होने का अनुमान है (सारणी II.3)। 2010-11 में राजस्व खाते में

सुधार का माध्यम राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि और राजस्व व्यय (जीडीपी के अनुपात के रूप में) में कमी रहने की संभावना है और इस प्रकार यहां अधिक संतुलन होगा। जीडीपी के अनुपात के रूप में कम पूंजीगत परिव्यय के साथ राज्य सरकारों के कम समेकित राजस्व घाटे से जीएफडी-जीडीपी अनुपात कम रहने की संभावना है।

II.11 2010-11 के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का अनुमानित संयुक्त वित्त संकेत करता है कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में मुख्य घाटा-संकेतक 2009-10 के उच्च स्तर से कम रहेंगे (सारणी II.3)।

### कंपनियों की बिक्री में वृद्धि उच्च बनी रही जो मांग में तेजी दर्शाती है

II.12 2010-11 की दूसरी तिमाही के दौरान निजी कंपनी क्षेत्र ने दृढ़ आर्थिक गतिविधियों में योगदान दिया और बदले में उसे दृढ़ बिक्री वृद्धि का लाभ मिला (सारणी II.4)। किंतु, वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान देखे गए हाल के शीर्ष कीतुलना में 2010-11 की दूसरी तिमाही के दौरान बिक्री की तुलना में मालसूची संचय निर्माण कम था (सारणी II.3)। निजी कंपनी क्षेत्र के पीएटी में कम वृद्धि की तुलना में, सरकारी वित्तेतर कंपनियों में काफी वृद्धि देखी गई जो कि तेल कंपनियों के मजबूत निष्पादन से प्रेरित थी।

II.13 अप्रैल-सितंबर 2010 के दौरान वित्तीय सहायता के लिए बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से संपर्क करने वाली कंपनियों के उच्च परिकल्पित

### सारणी II.3: प्रमुख राजकोषीय संकेतक

(जीडीपी का प्रतिशत)				
वर्ष	प्राथमिक घाटा	राजस्व घाटा	सकल राजकोषीय घाटा	बकाया देयताएं*
1	2	3	4	5
<b>केंद्र</b>				
2008-09	2.6	4.5	6.0	59.2
2009-10 सं.अ.	3.2	5.3	6.7	58.2
2010-11 ब.अ.	1.9	4.0	5.5	57.8
<b>राज्य #</b>				
2008-09	0.6	-0.2	2.4	26.2
2009-10 सं.अ.	1.6	0.8	3.4	26.2
2010-11 ब.अ.	1.0	0.4	2.9	25.8
<b>संयुक्त</b>				
2008-09	3.4	4.3	8.5	74.5
2009-10 सं.अ.	4.8	6.0	10.0	74.3
2010-11 ब.अ.	3.0	4.4	8.3	74.3

सं.अ. : संशोधित अनुमान। ब.अ. : बजट अनुमान।

\* : नवम्बर 2010 की रिपोर्ट 'गवर्नमेंट डेट स्टेटस ऐण्ड रोड अहेड', वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार के आधार पर चालू विनिमय दर पर बाह्य देयताएं शामिल हैं।

# : आंकड़े 27 राज्यों के हैं।

स्रोत: ऋणात्मक चिह्न अधिशेष दर्शाता है।

**सारणी II.4: निजी कारपोरेट क्षेत्र : वित्तीय निष्पादन**

(वृद्धि दर/अनुपात प्रतिशत में)

मद	2008-09				2009-10				2010-11	
	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कंपनियों की संख्या	2500	2386	2486	2561	2530	2531	2562	2565	2546	2586
बिक्री	29.3	31.8	9.5	1.9	-0.9	0.1	22.5	29.1	24.2	18.7
अन्य आय*	-8.4	-0.6	-4.8	39.4	50.2	6.0	7.4	10.3	-21.2	58.5
व्यय	33.5	37.5	12.6	-0.5	-4.4	-2.5	20.6	30.7	29.0	19.9
गिरावट संबंधी प्रावधान	15.3	16.5	16.8	19.6	21.5	20.7	21.6	20.1	19.9	16.8
सकल लाभ (पीबीआईटी)	11.9	8.7	-26.7	-8.8	5.8	10.9	60.0	36.7	8.2	10.3
ब्याज भुगतान	58.1	85.3	62.9	36.5	3.7	-1.0	-12.3	-2.9	26.9	5.9
कर पश्चात लाभ	6.9	-2.6	-53.4	-19.9	5.5	12.0	99.3	44.0	2.4	10.8
<b>चयनित अनुपात</b>										
बिक्री की तुलना में विक्रेय माल में परिवर्तन#	2.9	2.2	-1.7	-1.8	0.6	2.3	0.8	1.1	2.9	1.0
बिक्री की तुलना में सकल लाभ	14.5	13.5	11.0	13.7	15.7	14.9	14.3	14.6	13.9	13.6
बिक्री की तुलना में कर पश्चात लाभ	9.7	8.6	5.3	8.1	10.2	9.4	8.8	9.0	8.6	8.5
बिक्री की तुलना में ब्याज	2.4	2.9	3.8	3.2	2.8	3.1	2.7	2.4	2.9	2.7
सकल लाभ की तुलना में ब्याज	16.8	21.5	34.6	23.3	18.0	20.5	19.1	16.6	21.1	19.9
ब्याज कवरेज (टाईम)	6.0	4.6	2.9	4.3	5.6	4.9	5.2	6.0	4.7	5.0

# : इस मद को स्पष्टतया दशनिवाली कंपनियां।

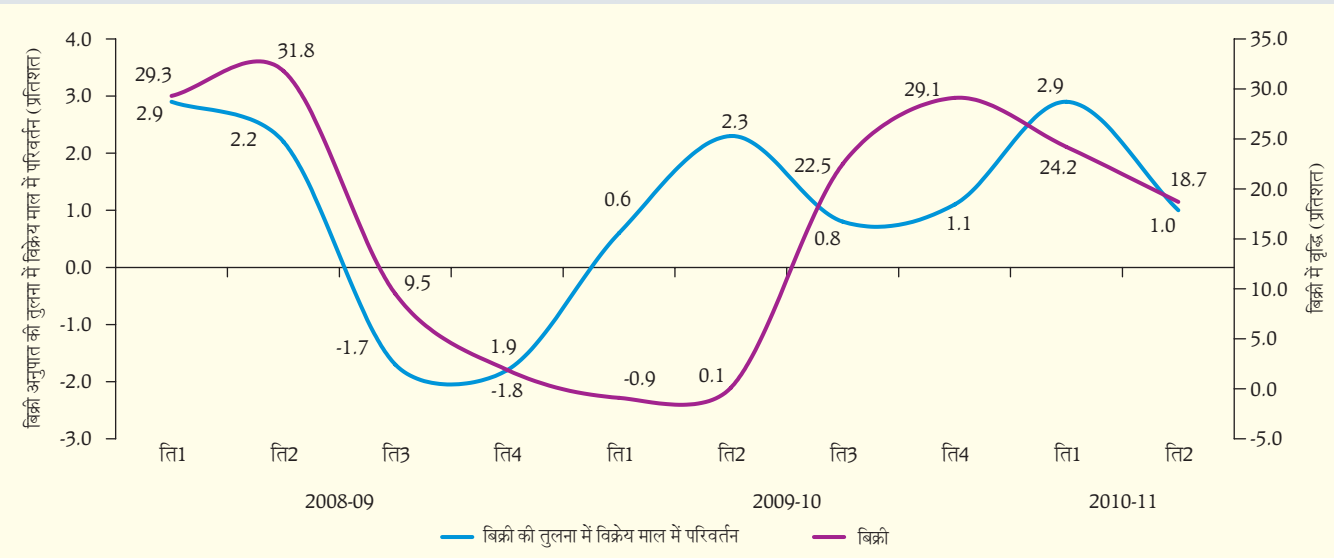
\* : अन्य आय में असाधारण आय/व्यय शामिल नहीं हैं यदि इन्हें स्पष्टतया सूचित किया गया हो।

**टिप्पणी:** वृद्धि दर समान कंपनियों के एक सेट के लिए पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि की तुलना में समीक्षाधीन अवधि के लिए स्तर में होने वाले प्रतिशत घट-बढ़ हैं।

पूंजीगत व्यय में दिखे अनुसार, निवेशी की मजबूत इच्छा स्थिर पूंजी निर्माण की अनुकूल संभावना दर्शाती है। 2010-11 की पहली छमाही में, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं ने 338 परियोजनाओं को सहायता स्वीकृत की थी जिसमें 2,42,000 करोड़ रुपये की राशि शामिल थी जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 251 परियोजनाओं को 2,31,000 करोड़ रुपये की राशि की सहायता स्वीकृत की गई थी। क्षेत्रवार असंतुलनों के कारण ढांचागत नीतियां आवश्यक हैं

II.14 निजी उपभोग में उछाल ने आंशिक रूप से कम आधार प्रभाव दर्शाया और इसीलिए यह अब तक कोई व्यापक आधार के मांग पक्षीय दबाव का संकेत नहीं देता है। क्षेत्रवार मांग-आपूर्ति असंतुलन के कारण, आपूर्ति की स्थिति सुधारने के लिए समग्र स्तर पर मांग दबाने वाले किसी उपाय के बजाय ढांचागत नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। निजी उपभोग व्यय में दृढ़ वृद्धि से आंशिक रूप से आपूर्ति पक्षीय बाधाओं की दृष्टि से कृषि के पक्ष में व्यापार शर्तों में परिवर्तन और

**चार्ट II.3: बिक्री में वृद्धि और बिक्री अनुपात की तुलना में विक्रेय माल में परिवर्तन (प्रतिशत)**



## **मौद्रिक नीति वक्तव्य 2010-11**

*समष्टिआर्थिक और मौद्रिक गतिविधियां  
तीसरी तिमाही की समीक्षा 2010-11*

एमजीएनआरईजीए जैसे सरकारी कार्यक्रम के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दिखती है। किंतु, आधार प्रभाव कम हो जाने से, अंतिम उपभोग व्यय में स्थिर वृद्धि के साथ ही कंपनियों के बिक्री-वृद्धि में हाल की गति अनिश्चित हो जाएगी। सरकार द्वारा राजकोषीय मजबूती पर दिए गए बल के कारण, स्थिर पुंजी निर्माण में सरकार का अंशदान बढ़ने के बावजूद वृद्धि में सरकारी अंतिम उपभोग व्यय तुलनात्मक

रूप से कम हो जाएगा। यदि राजकोषीय मजबूती में स्थिरता आती है तो उच्च वृद्धि के साथ कम मुद्रास्फीति की स्थिति आ सकती है। अल्पावधि संदर्भ में, समग्र आर्थिक विकास में बाह्य क्षेत्र का योगदान बढ़ाने के लिए भारत का नीतिगत विकल्प तेजी से बढ़ती उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में निर्यात में और विविधता लाने पर बल देना हो सकता है।